(घ) क्या यह भी सच है कि विज्ञान भवन में शिखर सम्मेलन के दौरान लगे श्रवण यन्त्र माध्यम से हिन्दी अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) दिल्ली में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पूर्व-स्थापित अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनश तथा अरबी में साथ-साथ अनुवाद की और प्रलेख तैयार करने की व्यवस्था की गयी थी। सम्मेलन कक्ष से बाहर प्रदर्शन तथा प्रचार के लिए हिन्दी का प्रयोग किया गया था।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का उत्थान

9179. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के उत्थान की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के रेल कर्मचारियों के मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न रेलवे पदों में भर्ती एवं पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों के सम्बन्ध में तथा रेलवे स्टेशनों पर खानपान और वेंडिंग के छोटे-मोटे ठेके देने में उनका हिस्सा सुनिश्चित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिए सरकार की नीति का कारगर ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेल मन्त्रालय में पहले ही पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। इस प्रयोजन के लिए रेल मन्त्रालय में एक पूर्ण आरक्षण कक्ष कार्य कर रहा है तथा रेल मन्त्रालय के अधीन क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन यूनिटों में भी एक आरक्षण कक्ष कार्य करता है जिसका प्रमुख एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रेल कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर सुलभ कराने के लिए प्रवरण पूर्ण कोचिंग और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अलावा इन समुदायों के लिए कुछ कोटियों में आरक्षित पदों के लिए एक बार अनुत्तीर्ण हुए कर्मचारियों में से श्रेष्ठतम कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है ताकि वे अपेक्षित मानक तक पहुंच सकें। क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों में आरक्षित कोटि की कमी को पूरा करने के लिए क्रमिक त्वरित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

Pension to widows of Railway Employees

9180. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway employees retired after 1 April, 1979 were given pension @ 50 per cent of pay;

(b) whether it is a fact that widows of such employees were granted the same amount of pension only upto seven years and thereafter it was substantially reduced; and

(c) if so, whether Government propose to give on humanitarian ground the same amount of pension to widows as their living husbands till their death and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY) : (a) No. The percentage of pension varies on the basis of the qualifying service and the average emoluments at different slabs.

(b) No. Under certain circumstances, family pension is paid for a period of 7 years at the enhanced rate of twice the normal

entitlement or 50% of the pay last drawn, whichever is less. Thereafter, the family pension is paid at normal rates.

(c) In such matters, the orders issued by the Ministry of Finance are adopted on the Railways also. Liberalisation in the Pension Scheme is generally considered in close consultation with the Ministry of Finance.

Holding of Regional Commonwealth Summit

9181. SHRI M. RAMGOPAL REDDY :
SHRI SUBHASH YADAV :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to convene the Regional Summit of Commonwealth Heads of Governments in November, 1983 in New Delhi;

(b) if so, the details of Heads of the States who are likely to participate;

(c) subjects likely to be discussed; and

(d) the dates, if any, finalised for the Summit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM) : (a) The biennial meeting of Commonwealth Heads of Government (CHOGM) will be held in Delhi this year. This is different from the regional meeting.

(b) The Heads of the following 43 governments which are full members of the Commonwealth are entitled to participate :

1. Antigua and Barbuda
2. Australia
3. Bahamas
4. Bangladesh
5. Barbados
6. Belize
7. Botswana
8. Britain
9. Canada
10. Cyprus
11. Dominica
12. Fiji
13. The Gambia
14. Ghana
15. Grenada
16. Guyana
17. Inaia
18. Jamaica
19. Kenya
20. Kiribati
21. Lesotho
22. Malawi
23. Malaysia
24. Malta
25. Mauritius
26. New Zealand
27. Nigeria
28. Papua New Guinea
29. St. Lucia
30. Seychelles
31. Sierra Leone
32. Singapore
33. Solomon Islands
34. Sri Lanka
35. Swaziland
36. Tanzania
37. Tonga
38. Trinidad and Tobago
39. Uganda
40. Vanuatu
41. Western Samoa
42. Zambia
43. Zimbabwe.

(c) In accordance with established practice, the Commonwealth Secretary-General in consultation with the member countries circulates details of a provisional agenda about 10 weeks in advance of the meeting. This is considered by a meeting of officials the day